

(n1/1200/nk-ru)

PAPERS LAID ON THE TABLE

1201 hours

HON. SPEAKER: Now, the House will take up Papers to be laid on the Table.

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल विजय कुमार सिंह) (सेवानिवृत्त) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपकी अनुमति से श्रीमती सुषमा स्वराज जी की ओर से सामूहिक संहार के आयुध और उनकी परिदान प्रणाली (विधिविरुद्ध क्रियाकलापों का प्रतिषेध) अधिनियम, 2005 की धारा 26 की उप धारा (3) के अंतर्गत सामूहिक संहार के आयुध और उनकी परिदान प्रणाली (विधिविरुद्ध क्रियाकलापों का प्रतिषेध कार्यान्वयन नियम, 2016 जो 8 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं.का.का.नि. 672 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION (RAO INDERJIT SINGH): I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Lakshadweep Building Development Board, Kavaratti, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Lakshadweep Building Development Board, Kavaratti, for the year 2015-2016.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(3) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(i) Review by the Government of the working of the Nagpur Metro Rail Corporation Limited, Nagpur, for the year 2015-2016.

(ii) Annual Report of the Nagpur Metro Rail Corporation Limited, Nagpur, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(4) A copy of the Annual Statement (Hindi and English versions) of out of turn discretionary allotments of General Pool Residential Accommodation made in terms of the guidelines dated 17.11.1997 for 5% vacancies occurring in each Type of General Pool Residential Accommodation in a Calendar year for the year 2016.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT (SHRI BANDARU DATTATREYA): I beg to lay on the Table a copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (2) of Section 7 of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952:-

(i) The Employees' Provident Funds (Third Amendment) Scheme, 2017 published in Notification No. G.S.R.298(E) in Gazette of India dated 29th March, 2017.

(ii) The Employees' Provident Funds (Seventh Amendment) Scheme, 2017 published in Notification No. G.S.R.299(E) in Gazette of India dated 29th March, 2017.

(iii) The Employees' Pension (Seventh Amendment) Amendment Scheme, 2017 published in Notification No. G.S.R.300(E) in Gazette of India dated 29th March, 2017.

(iv) The Employees' Deposit Linked Insurance (Second Amendment) Amendment Scheme, 2017 published in Notification No. G.S.R.301(E) in Gazette of India dated 29th March, 2017.

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस.अहलुवालिया): अध्यक्ष महोदया, मैं आपकी अनुमति से श्री विजय गोयल जी की ओर से राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान अधिनियम, 2012 की धारा 32 की उप धारा (3) के अंतर्गत राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान का पहला परिनियम (तीसरा संशोधन), परिनियम 2017 जो 31 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं.सा.का.नि. 310(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (COL. RAJYAVARDHAN RATHORE (RETD.)): On behalf of Shri Dharmendra Pradhan, I beg to lay on the Table a copy of Notification No. S.O. 753(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 6th March, 2017, regarding making Aadhaar mandatory for availing benefit under Pradhan Mantri Ujjwala Yojana under sub-section (2) of Section 58 of the Aadhaar (targeted Delivery of Financial and other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016.

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री, प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपकी अनुमति से सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 की धारा 14 की उपधारा (3) के अंतर्गत केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस.अहलुवालिया): अध्यक्ष महोदया, मैं आपकी अनुमति से श्रीमती निर्मला सीतारमण जी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

- (1) (एक) ईईपीसी इंडिया (भूतपूर्व इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल), कोलकाता के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
- (दो) ईईपीसी इंडिया (भूतपूर्व इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल), कोलकाता के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CULTURE AND MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TOURISM (DR. MAHESH SHARMA): I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Culture Fund, for the years 2013-2014 and 2014-2015, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Culture Fund, for the years 2013-2014 and 2014-2015.
- (2) Two statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनोज सिन्हा) : अध्यक्ष महोदया, मैं भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 की धारा 37 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ :-

- (1) दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं सेवा की गुणवत्ता और उपभोक्ता संरक्षण (एड्रेसेबल सिस्टम्स) के मानक विनियम, 2017 जो 3 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 21-5/2016-बीएंडसीएस में प्रकाशित हुए थे।
- (2) दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं अंतर्संबंध (एड्रेसेबल सिस्टम्स) विनियम, 2017 जो 3 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 21-4/2016-बीएंडसीएस में प्रकाशित हुए थे।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI S.S. AHLUWALIA): On behalf of Shri Mukhtar Abbas Naqvi, I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Haj Committee of India, Mumbai for the year 2015-2016, together with Audit Report thereon.
(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government on the Audited Accounts of the Haj Committee of India, Mumbai for the year 2015-2016.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Maulana Azad Education Foundation, New Delhi, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Maulana Azad Education Foundation, New Delhi, for the year 2015-2016.

(4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): अध्यक्ष महोदया, मैं आपकी अनुमति से भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 48 की उप धारा (3) के अंतर्गत भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारिवृंद) संशोधन नियम, 2017 जो 23 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 282 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिभाई चौधरी): अध्यक्ष महोदया, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

- (1) (एक) एमएसएमई-टूल रूम (सेंट्रल टूल रूम), लुधियाना के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एमएसएमई-टूल रूम (सेंट्रल टूल रूम), लुधियाना के वर्ष 2015-2016 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI RAJEN GOHAIN): I beg to lay on the Table a copy of the Railway Claims Tribunal (Procedure) Amendment Rules, 2017 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.332(E) in Gazette of India dated th April, 2017 under sub-section (3) of Section 30 of the Railway Claims Tribunal Act, 1987.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SHIPPING (SHRI PON RADHAKRISHNAN): I beg to lay on the Table a copy of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules, 2017 (Hindi and English versions) published in Notification No.

G.S.R.248(E) in Gazette of India dated 15th March, 2017 under sub-section (2) of Section 9 of the National Highways Act, 1956.

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णपाल गुर्जर):अध्यक्ष महोदया, मैं डॉ. संजीव बालियान जी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

- (1) (एक) नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
(दो) नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

.....

(o1/1205/rbn/sk)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI S.S. AHLUWALIA): On behalf of Shri Y.S. Chowdary, I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Consultancy Development Centre, New Delhi, for the year 2015-2016, along with Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Consultancy Development Centre, New Delhi, for the year 2015-2016.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

- - - - -

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL AVIATION (SHRI JAYANT SINHA): I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indira Gandhi Rashtriya Uran Akademi, Rae Bareli, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indira Gandhi Rashtriya Uran Akademi, Rae Bareli, for the year 2014-2015.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indira Gandhi Rashtriya Uran Akademi, Rae Bareli, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indira Gandhi Rashtriya Uran Akademi, Rae Bareli, for the year 2015-2016.

(4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

- - - - -

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES (SHRI BABUL SUPRIYO): Madam Speaker, I wish you a very happy birthday.

I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 619A of the Companies Act, 1956:-

(a) (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the Tungabhadra Steel Products Limited, Tungabhadra Dam, for the year 2015-2016.

(ii) Annual Report of the Tungabhadra Steel Products Limited, Tungabhadra Dam, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(b) (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the Hindustan Cables Limited, Kolkata, for the year 2015-2016.

(ii) Annual Report of the Hindustan Cables Limited, Kolkata, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at item No. (a) of (1) above.

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री महेन्द्र नाथ पाण्डेय): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा राज): माननीय अध्यक्ष जी, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूँ :-

- (1) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कार्पोरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, नई दिल्ली के वर्ष 2015-16 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कार्पोरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, नई दिल्ली के वर्ष 2015-16 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

1207 hours

SECRETARY-GENERAL: Madam Speaker, I have to report a message received from the Secretary-General of Rajya Sabha:--

“In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on the 10th April, 2017 agreed without any amendment to the Constitution (Scheduled Castes) Orders (Amendment) Bill, 2017 which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 23rd March, 2017. ”

LEAVE OF ABSENCE FROM SITTINGS OF THE HOUSE

1207 hours

HON. SPEAKER: The Committee on Absence of Members from the Sittings of the House in their Eighth Report, presented to the House on 11th April, 2017, have recommended that leave of absence from the sittings of the House be granted to the Members as indicated in the Report.

- | | | |
|----|-----------------------------|--------------------------|
| 1. | Shri Vinod Khanna | 31.01.2017 to 09.02.2017 |
| | | & |
| | | 09.03.2017 to 12.04.2017 |
| 2. | Shri Rayapati Sambasiva Rao | 09.03.2017 to 30.03.2017 |

Is it the pleasure of the House that leave as recommended by the Committee be granted?

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

HON. SPEAKER: Leave is granted. The Members will be informed accordingly.

COMMITTEE ON PUBLIC ACCOUNTS
74th Report

PROF. K.V. THOMAS (ERNAKULAM): I beg to present the 74th Report (Hindi and English versions) of the Public Accounts Committee (2016-17) on the subject 'XIX Commonwealth Games 2010'.

**COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND
RESOLUTIONS**
Minutes

DR. M. THAMBI DURAI (KARUR): I beg to lay on the Table the Minutes (Hindi and English versions) of the Twenty-ninth to Thirty-third sittings of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions held during the current Session.

**COMMITTEE ON WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND
SCHEDULED TRIBES**
11th Report

DR. KIRIT P. SOLANKI (AHMEDABAD): Madam Speaker, I wish you a very happy birthday.

I beg to present the Eleventh Report (Hindi and English versions) of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes (2016-17) on 'Reservation for and Employment of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL)' pertaining to the Ministry of Communications (Department of Telecommunications).

STANDING COMMITTEE ON EXTERNAL AFFAIRS
Statement

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): I beg to lay on the Table the statement (Hindi and English versions) showing Further Action Taken by the Government on the recommendations contained in the Tenth Report (16th Lok Sabha) on the action taken by the Government on the recommendations contained in the Sixth Report on Demands for Grants of the Ministry of External Affairs for the year 2015-16.

शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति
17वां प्रतिवेदन

श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी (अहमदनगर): माननीय अध्यक्ष जी, मैं 'संपदा महानिदेशालय का कार्यकरण, सीपलडल्ल्यूडी और एनबीसीसी द्वारा सरकारी आवासीय भवनों तथा अन्य भवनों का विनिर्माण तथा अनुरक्षण' विषय पर शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति (2016-17) का 17वां प्रतिवेदन (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

**STATEMENTS RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF
RECOMMENDATIONS IN 6TH AND 11TH REPORTS OF
STANDING COMMITTEE ON EXTERNAL AFFAIRS -- LAID**

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (GEN. VIJAY KUMAR SINGH (RETD.)): On behalf of Shrimati Sushma Swaraj, I beg to lay the Statement

(1) on the status of implementation of the recommendations contained in the 6th Report of the Standing Committee on External Affairs on Demands for Grants (2015-16) pertaining to the Ministry of External Affairs.

(2) on the status of implementation of the recommendations contained in the 11th Report of the Standing Committee on External Affairs on Demands for Grants (2016-17) pertaining to the Ministry of External Affairs.

**STATEMENT RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF
RECOMMENDATIONS IN 16TH REPORT OF STANDING
COMMITTEE ON LABOUR -- LAID**

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP (SHRI RAJIV PRATAP RUDY): I beg to lay the Statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 16th Report of the Standing Committee on Labour on Demands for Grants (2016-17) pertaining to the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship.

**STATEMENT RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF
RECOMMENDATIONS IN 237TH REPORT OF STANDING
COMMITTEE ON TRANSPORT, TOURISM AND CULTURE --
LAID**

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL AVIATION (SHRI JAYANT SINHA): I beg to lay a Statement on the status of implementation of the recommendations contained in the 237th Report of the Standing Committee on Transport, Tourism and Culture on the Action Taken by the Government on the Observations/Recommendations contained in the 230th Report of the Committee on the issues related to security at Airports in India pertaining to the Ministry of Civil Aviation.

(p1/1210/ksp/rjs)

**STATEMENTS RE: STATUS OF IMPLEMENTATION OF
RECOMMENDATIONS IN 265TH, 270TH AND 273RD REPORTS OF
STANDING COMMITTEE ON INDUSTRY – LAID**

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES (SHRI BABUL SUPRIYO): Madam, I beg to lay the following statements regarding:

- (1) the status of implementation of the recommendations contained in the 265th Report of the Standing Committee on Industry on Demands for Grants (2015-16) pertaining to Department of Heavy Industry, Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises.

- (2) the status of implementation of the recommendations contained in the 270th Report of the Standing Committee on Industry on Demands for Grants (2015-16) pertaining to Department of Heavy Industry, Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises.
- (3) the status of implementation of the recommendations contained in the 273rd Report of the Standing Committee on Industry on Demands for Grants (2016-17) pertaining to Department of Heavy Industry, Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises.

MATTERS UNDER RULE 377 – LAID

1211 hours

HON. DEPUTY SPEAKER: Hon. Members, the matters under Rule 377 shall be laid on the Table of the House. Members who have been permitted to raise matters under Rule 377 today and are desirous of laying them may personally hand over the text of the matter at the Table of the House within 20 minutes. Only those matters shall be treated as laid for which text of the matter has been received at the Table within the stipulated time. The rest will be treated as lapsed.

Re: Regarding inclusion of aborigines of Santhal Pargana in the list of Scheduled Tribes

SHRI NISHIKANT DUBEY (GODDA): I refer the matter raised under Rule 377 regarding inclusion of Khetauri, Ghatwal-Ghatwar and others as Scheduled Tribes in Parliament and received a reply from Hon'ble Minister of Tribal Affairs. But, amidst all of this, no development has taken place in this regard so far.

It is thus that I want to place a piece of great historical record - a book titled: "The Little World of an Indian District Officer", written by R.Carstairs and published by Macmillan & Co., London in 1912. In this book there is a detailed, historical record of the fact that the Santhal Pargana was created and named in 1855, and it was the youngest of the Bengal districts. The writer provides a wonderful account and description of the Ghatwals (guardians of the passes) and the Khetowrie (Khetauri) and how at the time of the Permanent settlement in 1790, every part of the territory was occupied. The details point out that at the time of the Permanent Settlement there was NOT a single Sonthal in the whole of this area. "Shunyas, Khetowries, Hindoos, Mahomedans, Highlanders - yes, but Sonthals, no".

It is a fact that when these findings were recorded and when the book in question was published, the nomenclature of Scheduled Castes and Tribes did not exist in the context of what it means administratively today. Thus the aborigines of the region are the ones who are deprived of their rightful status and claim to be recognized as Scheduled Tribes.

(ends)

Re: Need to run a direct train between Surat and Mumbai

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (मेहसाणा) :

Re: Need to stop ongoing survey by ONGC in Mumbai High at B-157 and give compensation to fishermen for the loss

SHRI CHINTAMAN NAVASHA WANGA (PALGHAR): ONGC has started seismic survey in Mumbai High at B-157, where thousands of fishermen are engaged in fishing to earn their daily bread. However, ONGC has floated tender to Dolphin company to do seismic survey for ONGC where company has prohibited fishing for 3 to 4 months at B-157 block. This is fifth survey of ONGC. Previously survey was undertaken on four occasions. The fishermen are not allowed to do fishing at neighbouring open sea.

This has created a lot of inconvenience to entire fishing business. The fishing boats are anchored, the working fishing class is idle, the ancillary class like fish transporter, ice suppliers, marketing is affected and there is loss of crores of rupees.

I, therefore, request the government to stop ONGC Survey in Mumbai High at B-157 and give compensation to fishermen.

(ends)

**Re: Need to provide a stoppage of Jan Shatabdi Express
(Train No. 12069/70) at Bilha Railway Station in Bilaspur
parliamentary constituency, Chhattisgarh**

श्री लखन लाल साहू (बिलासपुर):

Re: Need to review the list of Scheduled Tribes and delete the ineligible tribes not fulfilling the fixed norms from the list

श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा (भरुच) :

**RE: Need to set up Skill Development Centres in Dibrugarh,
Assam**

SHRI RAMESHWAR TELI (DIBRUGARH): My constituency Dibrugarh has a large number of tribal population. Majority of this tribal people are engaged in agricultural activities. The poor economic condition of the tribal people has forced them to live in utter poverty and penury. The Ministry of Tribal Affairs provides funds to TRIFED and National Scheduled Tribes Finance and Development Corporation (NSTFDC) to implement various schemes for skill and entrepreneurial development programme. I, therefore, urge upon the Hon'ble Minister for Tribal Affairs to open centres for various skill development programmes in my constituency Dibrugarh so that the poor tribal youths can take up jobs or start their own business.

(ends)

Re: Need to accord approval to the proposal for setting up a new steel plant at Chatra in Jharkhand

श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा) :

Re: Need to reduce wastage of food

SHRI RATTAN LAL KATARIA (AMBALA): According to an estimate, there is a waste of food grains, fruits and vegetables amounting to Rs. 60,000 crore every year in our country. In the same way, there is wastage of Rs. 60,000 crore food waste in our country. Therefore, hon'ble Prime Minister has called upon the countrymen to stop wastage of food. United Nations through its sustainable development goals have also launched a sustainable consumption and production of food. Therefore, I urge the Minister for Consumer Affairs, Food and Public Distribution that issue of food wastage may be taken up so that by 2030 we may be able to halve per capital national food waste at the retail and consumer level and reduce food losses along production and supply chains including post harvest losses. It is must in our country where 75% of rural and 50% of urban population is covered under PDS. Implementation of National Food Security Act effectively may be game changer in the life of poor people and we may be able to provide more food to our poor countrymen.

(ends)

Re: Need to enhance the amount of rehabilitation package for families displaced from Sariska, Ranthambhore and Mukundra Hills Tiger Reserves in Rajasthan

डॉ. मनोज राजोरिया (करौली-धौलपुर):

RE; Need to construct adequate number of mobile towers in Goa

ADV. NARENDRA KESHAV SAWAIKAR (SOUTH GOA): Goa with a population of 14.57 lakh have 144 BSNL Telephone Exchanges. The total number of Landline customers is 11,6355, while the number for broadband customer is 53,869. The number of Mobile customers stand at 180,4 5 and the number of WLL customers is 7986. Keeping these facts in view, the existing 374 Mobile Towers, including both 2G and 3G are considered to be inadequate besides their poor service quality. These have led to serious problems in the entire Goa, particularly the rural areas of South Goa. There is no proper connectivity and there is increasing number of call drop. Goa being an important tourist destination, both for domestic and foreign tourists, I would strongly urge upon the Government to look into the problem and immediately arrange for construction of adequate number of mobile towers.

(ends)

Re: Need to accord Central University status to University of Rajasthan

श्री रामचरण बोहरा (जयपुर शहर):

Re: Problems being framed by people living in remote and inaccessible areas situated near international border

COL. SONARAM CHOUDHARY (BARMER): Border Area Development Programme (BADP) was initiated during 7th Five Year Plan period to meet the special developmental needs and well being of the people living in remote and inaccessible areas situated near international border through provision of infrastructure and promotion of sense of security among the border population. As per guidelines, works can be undertaken in the villages located within 0-20 kms which was amended to include villages upto a distance of 0-50 kms. which is a welcome step. However, there is a rider that works beyond 0-20 kms. can only be taken after "SATURATION" of villages within 0-20 kms. There are numerous development activities. Most works of development have been done in 0-20 kms. areas but bureaucrats are not paying heed to our suggestions. Member of Parliament is not Member of either District Level Committee (DLC) as well as State Level Screening Committee (SLSC). There are 4 districts in the border areas of Rajasthan and represented by 3 MPs being myself from Barmer & Jaisamer Distts., S/Shri Arjun Meghwal (Bikaner) and Nihal Chand (Sri Ganganagar) have written letters and had personal meetings with the Hon'ble Home Minister four times and officials of Ministry of Home Affairs as recommended by Home Minister drawing attention to the specific needs of the bordering desert areas of Rajasthan. I also raised this matter in Lok Sabha during Zero Hour on 4th March, 2015 and through Questions on several occasions. I am sorry to say that

Hon'ble Home Minister and Minister of State in Ministry of Home Affairs have intention to make MPs member of District Level Committee and State Level Screening Committee but every time our suggestions were scuttled down by bureaucrats in position for reasons best known to them. Certain proposals of development works are prepared by Border Management Deptt. New Delhi and State Govt. which allegedly stinks of corruption. I want to mention here that two senior officials at State level in Rajasthan have been suspended but nothing happened at Central Government level officials who are allegedly involved in this episode. I urge the Hon'ble Prime Minister through Madam Speaker, to look into this as 100% funds are provided by Central Govt. under BADP and are being misused in connivance with officials at the level of Govt. of India and Govt. of Rajasthan. I, therefore, recommend the following- a) Distance is more in a large number of Blocks in the desert districts of Rajasthan and the depth of Blocks being in the range of 100-150 kms and as such should be allowed to be taken up in villages upto 50 kms and word "SATURATION" should be removed from the guidelines so that works can be undertaken under BADP, b) To have a meaningful monitoring, local MP, if not made Chairman as in the case of other Centrally sponsored schemes (DISHA) should at least be made Member of DLC and SLSC.

(ends)

**Re: Need to set up a separate Railway Zonal Headquarters and
office of IRCTC at Ranchi, Jharkhand**

श्री राम टहल चौधरी (राँची) :

Re: Need to evolve a mechanism to deal with stay orders given by courts

SHRIMATI DARSHANA VIKRAM JARDOSH (SURAT): There are huge number of cases which are stuck up with stay order in various courts of our country. Due to stay order, court cases are not proceeding further since a long time. This is a loophole of our independent judicial system. Many cases related to revenue of the Government are also stuck up with stay orders which block revenue of the Government.

Under this circumstances, I would like to request Central Government to make special law or mechanism so that, stay orders given by courts are applicable only for specific duration and after completion of the duration, stay order is automatically nulled. The duration of court stay orders should be decided by concerned courts according to merit of the case.

(ends)

Re: Alleged harassment of genuine citizens while updating National Register of Citizens in Assam

KUMARI SUSHMITA DEV (SILCHAR): The National Register of Citizens is in the process of being updated in Assam being funded by the Government of India with an aim to delete the names of illegal foreigners. Simultaneously, the local police is trying to detect suspected foreigners in Assam. This process is turning out to be extremely arbitrary in many cases where genuine citizens of India are being detained and harassed despite having valid proof of Citizenship. This is causing unrest and fear especially amongst the Bengali speaking people in Assam. Such arbitrary action must be stopped immediately by the Ministry of Home.

(ends)

**Re: Need to set up Trauma Centres at Kanakapura and
Channapatna in Karnataka**

SHRI D.K. SURESH (BANGALORE RURAL): National Highways (NH) 209 and 275 run through my Bangalore Rural constituency. NH 209 is from Bangalore to Dindigul in Tamil Nadu and nearly 120 Kms of this highway run through my Constituency. NH 275 is from Bangalore to Mysore and nearly 80 Kms of this highway run through my constituency. The traffic has increased on the highway and as a result the number of accidents and deaths are rapidly rising. The number of people died in fatal accidents on NH 209 and 275 only in the Ramanagara district area was 767 in three and a half years. Unfortunately, Trauma care is not available easily on the National Highway for long stretches as there are no major hospitals other than in Bangalore and Mysore. Therefore, I urge upon the Government to take immediate steps to set up Level II Trauma Centres at Kanakapura on NH 209 and at Channapatna on NH 275.

(ends)

Re: Need for a comprehensive law to prevent sale and export of harmful food stuff

SHRI MULLAPPALLY RAMACHANDRAN (VADAKARA): Of late an alarming situation has arisen in the health sector of Kerala and several other states across the country. It is distressing to note that incidence of lifestyle diseases like cancer, hypertension, diabetes, kidney ailments etc. are frighteningly on the increase. All studies go to show that apart from lack of proper exercise, the contamination in fruits, vegetables and other food stuff due to use of pesticides, insecticides and excessive chemical fertilizers are the main causes for this malaise. Large consignments of mangoes and other fruits exported to European and other countries are rejected on account of such contamination. Hence I request the Minister for Consumer Affairs to bring about a comprehensive law to prevent sale and export of such harmful food stuff and ensure stringent food safety.

(ends)

Re: Need to establish AIIMS at Sengipatti in Thanjavur district of Tamil Nadu

SHRI K. PARASURAMAN (THANJAVUR): I would like to urge the government to expedite setting up of AIIMS in Tamilnadu at Sengipatti in Thanjavur District. The proposal for establishment of AIIMS in Tamil Nadu was announced in the Union Budget 2015-2016. The Central Team constituted by the Ministry of Health and Family Welfare had visited Tamil Nadu as early as 23 - 25 April, 2015 to all the places identified by the Government of Tamil Nadu including the Sengipatti in Thanjavur district. The central team had also submitted its reports to the Government. However, so far the final decision regarding the location suited for this project has not been announced by the Government of India. It is further learnt that Sengipatti in Thanjavur District has been identified as the best suited location for setting up of AIIMS. Accordingly, our Hon'ble Chief Minister of Tamilnadu had already urged the Hon'ble Prime Minister of India on 27-02-2017 to expedite establishment of AIIMS at Sengipatti, in Thanjavur District. Thanjavur is the central part of the state and it covers Tiruvarur, Tiruchirappalli, Nagappatinam, Pudukottai, Ariyalur, Perambalur, Chidambaram, Cuddalore, Sivagangai and Karur districts. In case of setting up of AIIMS in this district, it would not only be beneficial to the population of above said districts but also cover the entire state. Therefore, I once again request the government to notify the proposed location of AIIMS at Sengipatti in Thanjavur District along with necessary financial sanction. (ends)

Re: Regarding upgradation of National Highway 209 in Tamil Nadu

SHRI M. UDHAYAKUMAR (DINDIGUL): National Highway 209 - Dindigul to Bangalore Via (Palani-Coimbatore-Sathyamangalam-Hasanur) constructed in the year 1950 connects Bangalore with Coimbatore and Dindigul. There is an increasing demand to widen this 268 km National Highway (NH) 209 from Dindigul - Tamil Nadu to Karnataka border because of the traffic and growth on the Dindigul Coimbatore-Bangalore section as it will ensure smooth flow of traffic.

Currently, the NH-83 (earlier known as NH 209) route is in a bad condition. It has numerous curves which pose a threat to motorists. The initial proposal is to widen the entire stretch into a four-lane road. The project has two sections: from Dindigul to Coimbatore and from Coimbatore to Karnataka border. The proposal will include four major bridges, 30 minor bridges, vehicular and passenger underpasses, and road over bridges and as many as six bypass roads between Dindigul and Coimbatore. The total project cost is estimated to be about Rs. 3,000 crores (excluding the land cost).

Meanwhile, it is learnt that the Central Government has approved widening of the road from Pollachi to Coimbatore though it is part of NH 83. The National Highways Authority of India awarded (NHDP IV), Ministry of Road Transport & Highways, New Delhi, an order worth Rs. 414,90,00,000/- (Rupees Four Hundred and Fourteen Crore Ninety Lakh only) towards "Rehabilitation and up-gradation of NH-

209 from Km. 123.550 to Km. 150.400 of Dindigul - Bangalore Road (Pollachi to Coimbatore Section) to four lane with paved shoulder in the State of Tamil Nadu under NHDP — IV on EPC basis “to be completed within a period of 24 months from the appointed date. It is learnt that the National Highways Authority of India (NHAI) has not yet finalised the feasibility study to widen National Highways 83 (earlier known as NH 209) from Dindigul to Pollachi which runs through Oddanchathiram, Palani and Udumalpet.

I request the Ministry of Road Transport & Highways to commence the work under National Highways Development Project for the entire stretch of NH 209. The bypasses are to be built in Oddanchathiram, Chatrapathi, Ayakkudi, Madathukulam, Udumalpet, provide service roads and bypass roads for the safe movement of local people along many highways.

Six bypasses, six rail-over bridges and two major bridges on Shanmuganadi river near Palani and the Amaravathi near Madathukulam must also be part of the project. Passenger and vehicular underpasses are also to be built in the project that will include service roads, rest areas and bus bays.

(ends)

Re: Need to release balance funds for setting up of four ITIs in Odisha

SHRIMATI PRATYUSHA RAJESHWARI SINGH (KANDHAMAL):
The State Government has availed 50% of the committed Central Financial Assistance of Rs.20.00 crores i.e. Rs. 8.10 crores towards capital expenditure for establishment 4 new ITIs at Bhandaripokhari in district Bhadrak, Daringbadi in district Kandhamal, Kotagarh in district Kandhamal and Kutra in district Sundargarh during financial year 2015-16. The Rural Works Department (RWD) has taken up civil construction of all the 4 ITIs with provision of Rs.10.00 crores during 2016-17.

I request the Minister of Minority Welfare Affairs to release the balance of 50% of the committed Central Financial Assistance of Rs. 20.00 crores so that civil construction and procurement of goods could be taken up.

(ends)

**Re: Need to prepare a list of approved engineering colleges in
Maharashtra**

SHRI GAJANAN KIRTIKAR (MUMBAI NORTH WEST):
Engineering Colleges get approval on the condition that they follow AICTE guidelines. In Maharashtra there are about 109 Engineering Colleges whose affiliation has been withdrawn because they were unable to follow all the guidelines of AICTE and many students are unable to appear for their final engineering.

The Central Government Institute had arranged a document compliance camp on the premises of VJTI College on 18th April, 2016. In this regard, I request the AICTE to publish the information about approved engineering colleges in Maharashtra and the number of seats per course for respective colleges and make it mandatory on the part of the colleges to display the list at the entrance of colleges.

In addition, in the academic year 2017—18, a Special Task Force can be created which will inspect the colleges which give admissions to students but have been disapproved and strict action should be taken against such colleges.

If the corrective action is taken, it will help many students from being cheated by fake engineering colleges.

(ends)

Re: Problems faced by Chilli farmers in Andhra Pradesh

SHRI JAYADEV GALLA (GUNTUR): I had raised this very issue on 30-3-2017, and expected Government of India to help Chilli farmers in Andhra Pradesh, but nothing has been done. This forces me to raise this issue again since situation is getting worse day-by-day.

When I mentioned this issue on 30-3-2017', farmers were getting Rs. 6,000 - 8,000/quintal for their produce which was much lower than last year price of Rs. 14000 - 15000/quintal. But, now, reports indicate that farmers are not getting even Rs, 5,000/quintal. So, farmers are now planning to store chillis in cold storage and sell their produce when they get a better price. But, banks are not giving them loans by mortgaging chillies which is the usual practice at the time of crisis. It is forcing them to go to private moneylenders who are charging interest at Rs. 2 - 3/month which is exorbitant from any point of view.

Secondly, they are not giving more than Rs. 1 ,500/quintal as loan. Banks officials are saying they have orders from higher authorities not to give loans to chilli farmers. This is sheer discrimination. I request Government of India to immediately direct banks to give loans to chilli farmers at 7% rate of interest, purchase chillies from farmers through Market Intervention Scheme by fixing MSP at Rs. 12,000/quintal, take steps to promote exports and provide cold storage facilities at market yards to store their produce during crisis without going to banks and, most importantly, there is immediate need to set up Chilli Board since chillis aren't getting attention from Spices Board. An independent Chilli Board would have addressed the current chilli crisis and sufferings of chilli farmers. (ends)

Re: Need to obtain Presidential assent to the Bill passed by Kerala Legislative Assembly

SHRI M.B. RAJESH (PALAKKAD): The Kerala Assembly had unanimously passed a Bill in 2011 to set up a tribunal to obtain compensation for the people of Plachimada village of Palakkad. The village was devastated due to over-exploitation of water by Coca-cola plant. The entire area became uncultivable and faced severe drinking water shortage. An expert committee appointed by the Government of Kerala estimated a loss of Rs. 216 crore to the people of that area and recommended to set up a tribunal. Though the Bill was passed 6 years ago, the Union Home Ministry has not yet sent the Bill for the Presidential assent.

I urge upon the Government to immediately send the Bill for Presidential assent.

(ends)

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Madam, what about 'Zero Hour'? ... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : आप सब बैठ जाइये। अभी कुछ नहीं होगा।

... (व्यवधान)

VALEDICTORY REFERENCE

1212 बजे

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, सोलहवीं लोक सभा का ग्यारहवां सत्र आज समाप्त हो रहा है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : इस बजट सत्र का पहला भाग माननीय राष्ट्रपति द्वारा केन्द्रीय कक्ष में दोनों सभाओं के एक साथ समवेत् सदस्यों को 31 जनवरी, 2017 को किए गए संबोधन के साथ प्रारंभ हुआ।

एक ऐतिहासिक कदम के रूप में वर्ष 2017-18 का केन्द्रीय बजट 1 फरवरी, 2017 को सामान्य और रेल बजट, दोनों बजटों को एक साथ मिलाकर पेश किया गया।

इस सत्र के दौरान कुल 29 बैठकें हुईं, जो 176 घंटे और 39 मिनट चलीं। इनमें से 7 बैठकें सत्र के पहले भाग में और 22 बैठकें दूसरे भाग में हुईं।

सभा ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की, जिसकी एक प्रति सभा पटल पर 31 जनवरी, 2017 को रखी गई। धन्यवाद प्रस्ताव पर 10 घंटे और 38 मिनट तक चली बहस के पश्चात् 7 मार्च, 2017 को धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया गया।

वर्ष 2017-18 के केन्द्रीय बजट पर चर्चा 8 और 9 फरवरी, 2017 को हुई, जो 9 घंटे 58 मिनट तक चली।

सभा 9 फरवरी, 2017 को स्थगित की गई, ताकि स्थायी समितियां विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के अनुदानों की मांगों की जांच कर सकें और उन पर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकें।

सत्रावकाश के पश्चात् बजट सत्र का दूसरा भाग 9 मार्च, 2017 को आरंभ हुआ।

दूसरे भाग के दौरान रेल, कृषि और किसान कल्याण, रक्षा तथा गृह मंत्रालयों की अनुदानों की मांगों के पूर्णतः स्वीकृत होने से पूर्व उन पर 26 घंटे से अधिक समय तक चर्चा हुई। वर्ष 2017-18 के लिए बजट (सामान्य) के संबंध में शेष मंत्रालयों की अनुदानों की अन्य

सभी बकाया मांगों को सभा में मतदान के लिए रखा गया और 20 मार्च, 2017 को ये पूरी-पूरी स्वीकृत हुई तथा संबंधित एप्रोप्रिएशन बिल भी पारित किया गया।

वर्ष 2016-17 के लिए सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स (रेलवे) और वर्ष 2013-14 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेलवे) एक्सेस डिमांड्स को पारित किया गया और संबंधित विनियोग विधेयक भी उसी समय पारित किया गया। वर्ष 2016-17 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य) को 3 घंटे 46 मिनट तक चली चर्चा के पश्चात् पारित किया गया और संबंधित एप्रोप्रिएशन बिल भी पारित किया गया।

सभा में 21 और 22 मार्च, 2017 को फाइनेंस बिल पर चर्चा हुई और इसे पारित किए जाने से पहले 8 घंटे और 41 मिनट तक चर्चा हुई। माननीय सदस्यगण वित्त वर्ष की समाप्ति से पूर्व पूरी बजट प्रक्रिया को पूरा करना हमारे सांसदों की उल्लेखनीय उपलब्धि रही है, जिसकी सराहना 5 अप्रैल, 2017 को भी यहां से की गयी है। इससे जन कल्याणकारी कार्यों के लिए 1 अप्रैल से धनराशि उपलब्ध हो गई थी।

(q1/1215/rps-kkd)

चालू सत्र के दौरान 24 सरकारी विधेयक इंट्रोड्यूस किए गए और कुल मिलाकर 23 विधेयक पारित किए गए। पारित किए गए कुछ महत्वपूर्ण विधेयक हैं - पेमेंट ऑफ वेजेज (अमेंडमेंट) बिल, 2017, स्पेसिफाइड बैंक नोट्स बिल, 2017, मैटरनिटी बेनिफिट (अमेंडमेंट) बिल, 2016, एडमिरैल्टी (ज्यूरिडिक्शन एंड सेटलमेंट ऑफ मेरीटाइम क्लेमस) बिल, 2016, एनिमी प्रॉपर्टी (अमेंडमेंट) बिल, 2016, कांस्टीट्यूशन (शिड्यूल्ड कास्ट्स) ऑर्डर्स (अमेंडमेंट) बिल, 2017, मेंटल हेल्थकेयर बिल, 2016, नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी, साइंस एजुकेशन एण्ड रिसर्च (सेकण्ड अमेंडमेंट बिल), 2016, फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट बिल, 2017, दि टैक्सेशन लॉज (अमेंडमेंट) बिल, 2016, मोटर वेहिकल्स (अमेंडमेंट) बिल, 2016, कांस्टीट्यूशन (123rd अमेंडमेंट) बिल, 2017, मानव रोगक्षम अल्पता विषाणु और अर्जित रोगक्षम अल्पता संरक्षण (निवारण और नियंत्रण) विधेयक, 2017।

विधायी क्षेत्र में इनके अलावा एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि जीएसटी से संबंधित चार विधेयकों - सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, बिल, 2017, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बिल, 2017, सेंट्रल गुड्स एण्ड सर्विसेज टैक्स (कम्पेनसेशन जो स्टेट्स) बिल, 2017 और यूनियन टेरिटरी गुड्स एण्ड सर्विसेज टैक्स बिल, 2017, का पारित होना भी है।

सत्र के दौरान 560 तारांकित प्रश्नों में से 136 से अधिक प्रश्नों के मौखिक उत्तर दिए गए। इस प्रकार, औसतन 4.68 प्रश्नों के उत्तर दिए गए। शेष तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर, 6,440 अतारांकित प्रश्नों के उत्तरों के साथ सभा पटल पर रखे गए।

सदस्यों ने प्रश्न काल के पश्चात् और सभा के औपचारिक कार्य के समापन के पश्चात् शाम को देर तक बैठकर लगभग 541 मैटर्स ऑफ अर्जेंट पब्लिक इम्पोर्टेंस के मामले उठाए। माननीय सदस्यों ने नियम 377 के अधीन भी करीब 494 मामले उठाए। इस सत्र के दौरान, विभागों से संबद्ध स्थायी समितियों ने 68 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए। सभा में एसडीजी के बारे में भी नियम 193 के अधीन अल्पकालिक चर्चा हुई और यह चर्चा अभी निरंतर है।

माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा सरकार कार्य के बारे में दिए गए पांच वक्तव्यों सहित, अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मंत्रियों द्वारा 51 वक्तव्य दिए गए। सत्र के दौरान संबंधित मंत्रियों ने करीब 1,864 पत्र सभा पटल पर रखे।

जहां तक प्राइवेट मेंबर्स बिजनेस का संबंध है, सत्र के दौरान गैर-सरकारी सदस्यों द्वारा विभिन्न विषयों पर 158 विधेयक पुरःस्थापित किए गए। श्री विन्सेंट एच. पाला द्वारा नौवें सत्र के दौरान पांच अगस्त, 2016 को पेश किए गए, सिक्स्थ शिड्यूल ऑफ दि कांस्टीट्यूशन (अमेंडमेंट) बिल, 2015 पर विचार किए जाने का प्रस्ताव को 10 मार्च, 24 मार्च और सात अप्रैल, 2017 को आगे चर्चा के लिए लिया गया। तथापि, विधेयक पर चर्चा सात अप्रैल को भी पूरी नहीं हुई।

जहां तक गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों का संबंध है, कर्मचारी भविष्य निधि के पेंशनभोगियों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन जी द्वारा 11 दिसम्बर, 2015 को छठे सत्र के दौरान पेश किए गए संकल्प, जिस पर आठवें और नौवें सत्र के दौरान

क्रमशः 6 मई और 29 जुलाई, 2016 को चर्चा की गयी थी, पर सत्र के दौरान आगे चर्चा 23 और 31 मार्च, 2017 को की गयी। तथापि, चर्चा 31 मार्च, 2017 तक पूरी नहीं हो पाई।

इस सत्र में व्यवधानों के कारण आठ घण्टे, 12 मिनट का समय व्यर्थ हुआ, लेकिन सभा ने 28 घण्टे और 40 मिनट देर तक बैठकर, अर्जेंट गवर्नमेंट बिजनेस पारित किया। इस तरह से, यह अत्यंत सार्थक और उत्पादक सत्र रहा जो हम सभी की साख के लिए भी बहुत-बहुत अनुकूल है।

(r1/1220/asa/rp)

मैं माननीय उपसभापति और सभापति तालिका (Panel of Chairmen) में शामिल अपने सहयोगियों का सभा के सुचारु रूप से संचालन में अपना सहयोग देने के लिए धन्यवाद करती हूं। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी, संसदीय कार्य मंत्री, विभिन्न दलों और समूहों के नेताओं और मुख्य सचेतकों तथा माननीय सदस्यों के प्रति भी उनके सहयोग के लिए कृतज्ञता व्यक्त करती हूं। मैं आप सभी की ओर से प्रेस और मीडिया के अपने मित्रों का भी धन्यवाद करना चाहूंगी। मैं इस अवसर पर महासचिव और लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को उनके द्वारा सभा को दी गई समर्पित और तत्काल सेवा के लिए धन्यवाद देती हूं। मैं सभा की कार्यवाही के संचालन में संबद्ध सभी एजेंसियों को उनके द्वारा प्रदान की गई सहायता के लिए भी धन्यवाद देती हूं। आप सभी को भी धन्यवाद है और मेरा विश्वास है कि इसी प्रकार हम देश के लिए काम करते रहेंगे।

माननीय सदस्यगण, आप कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं क्योंकि अब 'वन्दे मातरम्' की धुन बजाई जाएगी।

(The National Song was played.)

HON. SPEAKER: The House stands adjourned *sine die*.

1222 hours

The Lok Sabha then adjourned sine die.